जो पैसा दिया गया, उसमें से कैसे चार रुपया या दो रुपया लोगों ने खा लिया। यह कोई कांग्रेस कल्चर भी नहीं है कि यदि किसी गरीब आदमी को 50 रुपया मिले तो दो रुपये उसमें से कोई अपनी जेब में डाल ले। हमारे मिनिस्टर साहब ने साफ कहा है और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से या दिल्ली कार्पोरेशन की तरफ जो कुछ हो रहा है, वह आखिर सैन्ट्रल गवर्नमैंट और होम मिनिस्टर की तरफ से ही तो हो रहा है, हमको इस चीज को नहीं भूलना चाहिए और इनके बीच में कोई फर्क नहीं करना चाहिए कि कोई भी आदमी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। इस वास्ते जो कदम उठाए गए हैं अच्छे हैं और मैं होम मिनिस्टर से कहूंगा कि और जितनी सहूलियतें उन लोगों को दी जा सकती हैं वह दी जाएं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेड्डी जी का आभारी हूं कि इन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। आग नहीं लगे इस प्रकार का शिक्षण लोगों का होना चाहिए चाहे सिनेमा स्लाइड से या साइन बोर्ड से। और इस तरह की कोचिंग लगाकर लोगों को बताया जाए। जो उनको सहायता दी गई है, मैंने अभी बताया कि 3 दिन तक उनको खाने और कपड़े का इन्तजाम दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए, यह मैं उनसे कहने जा रहा हूं और वह किया जाएगा। साथ ही झुग्गी झोंपड़ी वालों को अच्छी तरह से रहने का और जिन्दगी की अन्य आसाइशें मिलें इसके लिए पानी की व्यवस्था,...

श्री मनी राम बागड़ी : दवाई और सफाई की व्यवस्था का भी इन्तजाम किया जाय।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जो आदमी मैडिकल ऐड के लिए जा रहे हैं उसके लिए अलग से मैडिकल हैल्प सैन्टर खोल दिया जायगा। जो लोग जले हैं उनको मामूली खारिश है, उसमें से दो लोग डिसचार्ज हो गए हैं। कोई डिसएबिल नहीं हुआ है। और अगर कोई हुआ है तो उसको ऐसा मुआवजा दिया जायगा जैसा कि डिसीज्ड पर्सन को दिया जाता है।

13.11 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Need to protect interests of the residents of Housing colonies in Chheda Nagar, Chembur and Garodia Nagar, Ghatkopar in Bombay

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East) : Sir, In my Constituency in North Bombay, there are two large private residential housing colonies at Chheda Nagar, Chembur and Garodia Nagar, Ghatkopar. Many private Housing Cooperative Societies had purchased plots from M/s Chheda and M/s Garodia respectively and constructed these residential buildings.

Before purchase of these lands, there Cooperative Societies have checked whether titles of ownership of these lands were clear and the Bombay Municipal Corporation had also epproved the building plans.

Suddenly the Salt Commissioner woke up and claimed the ownership of these lands where these buildings came up and served notices asking them to vacate.

It is surprising that the Salt Commissioner did not object when these buildings were under construction and when advance publicity was given regarding sale of these plots. It is even reported that the State Government had paid the so-called owners M/s Garodia and M/s Chheda, compensation for acquisition of some portion of these lands for State Highway etc. This step of Central Government has put the innocent residents in a fix as most of them have invested their life savings for these houses.

Central Government should immediately intervene in this matter and protect the interests of the residents.

(ii) Need for tightening up provisions of the Bonded Labour (Abolition) Act

SHRI MADHAVRAO SCINDIA (Guna) : Sir, Poor tribals of Raipur district of Madhya Pradesh still continue to suffer from inhuman bonded labour system. They are compelled to mortgage

[Shri Madhavrao Scindia]

their children who receive no wages other than food from their employers. On growing up, they are given a loan of about Rs. 200 for their marriage. As they are never able to repay the amount, they in turn, mortgage their children and the system of bonded labour continues.

These labourers, on an average, put in two mandays every day without respite. They are given no leave and lose their wages when they are unable to work due to illness. Continuous work makes a large majority of them develop peculiar humps and buffalo skin.

It is likely that landlords, taking advantage of some lacuna in the Bonded Labour (Abolition) Act, are able to exploit poor tribals and perpetuate this pernicious system.

I would like to urge upon the Government to take immediate steps to tighten up the provisions of the Bonded Labour (Abolition) Act, so as to ensure that no loopholes are left in it which may be taken advantage of by unscrupulous landlords to continue to exploit poor tribals.

(iii) Need to ban export of human skeletons

श्रीमती माधुरी सिंह (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में मूल मानव शरीरों का और उनके अस्थि-पिंजरों को महंगी कीमत में विदेशों में बेचने का धंधा जोरों पर चल रहा है। हर वर्ष लगभग 20,000 अस्थि-पिंजर विदेशों को निर्यात किए जाते हैं। अमरीका, इंगलैंड, कनाडा, आस्ट्रेलिया, हांगकांग, स्विट्जरलैंड आदि देशों में इनका आयात होता है। इनकी सबसे अधिक खपत अमरीका में हो रही है। कुछ देशों ने इस व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। भारत से नर-कंकाल सबसे अधिक आस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन भेजे जाते हैं। बिहार में यह व्यवसाय काफी जोरों पर है। हमारे देश में कई कंपनियां यह काम कर रही हैं। आजकल लाशों को नदी, कब्रों से और अस्पतालों से चुरा लिया जाता है।

मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि इस व्यवसाय पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगा दिया जाए। इससे हमारे देश की प्रतिष्ठा की हानि हुई है। यह आश्चर्य की बात है कि जानवरों की हड्डियों का निर्यात तो बन्द है, लेकिन मानव-कंकालों के निर्यात पर कोई रोक नहीं है।

आजकल वयस्क व्यक्ति का पूरा कंकाल विदेशों में लगभग 10,000 रुपए में पड़ता है, जबकि हमारे यहां यह 200 रुपए में प्राप्त कर लिया जाता है। अत: मैं सरकार से आग्रह करूंगी कि आर्थिक लाभ की परवाह न करते हुए हमारे देश की प्रतिष्ठा की दृष्टि से नर-कंकालों का निर्यात तुरन्त बन्द कर दिया जाए।

(iv) Need to pay compensation for the structural weaknesses in flats constructed at Prasad Nagar, Delhi by DDA and refund of escalated price charged from allottees

SHRI SURAJ BHAN (Ambala) : The DDA, through its multipronged process, has escalated the cost price of the 352 flats of Prasad Nagar, New Delhi. The construction of these flats was procrastinated to escalate the cost price. These flats were built in a single phase by the same contractor but the allotment was made in three phases.

With the second phase allotment, the cost price escalated by Rs. 5,000/- in contravention to what is mentioned in the brochure. There was no choice before the allottees but to accept the escalation. Another shocking fact was that what was exhibited in the Sample House was by and by withdrawn in quality and quantity. Tiles are conspicuously absent in the 256 flats allotted in the second and third phases.

The 'Tendered Specification' is a pledged document promising the allottees what they are expected to have. It is a pity that this document, along with many other important documents has been denied to the Residents' Welfare Association, Prasad Nagar II, New Delhi-5, despite their repeated requests.